Seventeenth Loksabha

>

Title: Regarding corporatization of Railway Production Unit.

श्रीमती सोनिया गांधी (रायबरेली): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूं । मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान सरकार की उस योजना की तरफ खींचना चाहती हूं जिसमें रेलवे की 6 उत्पादन ईकाइयों का कंपनीकरण किया जाना वाला है । इस योजना के प्रथम चरण में रायबरेली की मॉर्डन कोच फैक्ट्री होगी ।

अध्यक्ष महोदय, जो कंपनीकरण यानी कॉरपोरेटाइजेशन के असली मायने नहीं जानते हैं, मैं उन्हें यह बताने की इजाज़त चाहती हूं कि कंपनीकरण दरअसल निजीकरण की शुरुआत है । यह देश की अमूल्य सम्पत्ति कौड़ियों के दाम चंद निजी हाथों के हवाले करने की पहली प्रक्रिया है । इससे हज़ारों लोग बेरोजगार हो जाते हैं । असली चिंता तो इस बात की है कि सरकार ने इस प्रयोग के लिए रायबरेली की मॉर्डन कोच फैक्ट्री को चुना है, जो कि कई कामयाब परियोजनाओं में से एक है । इसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में यूपीए सरकार ने देश के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने, यानी 'मेक इन इंडिया' के लिए शुरू किया था । आज इस कारखाने में इसकी बुनियादी क्षमता से भी काफी ज्यादा उत्पादन हो रहा है । भारतीय रेलवे का यह सबसे आधुनिक कारखाना है और सबसे सस्ती कीमतों पर सबसे बेहतर रेलवे कोच बनाने के लिए मशहूर है । यह सबसे अच्छी ईकाइयों में से एक मानी जाती है, जिसकी स्थापना के समय से ही सरकारों ने इसमें बहुत पैसा लगाया है । अपनी कड़ी मेहनत से यह उपलब्धि हासिल करने वाले दो हजार से ज्यादा मजदूरों और कर्मचारियों को मैं इस सदन में बधाई देती हूं, लेकिन दुख की बात यह है कि अब उन सभी का और उनके परिवारों का भविष्य भारी संकट में है और किसी के लिए भी यह समझना मुश्किल है कि क्यों यह सरकार ऐसी औद्योगिक ईकाई का कंपनीकरण करना चाहती है?

अध्यक्ष महोदय, संसद में अलग से रेल बजट पेश करने की इतनी पुरानी परंपरा को पता नहीं इस सरकार ने अचानक क्यों खत्म कर डाला? लेकिन अब हम कंपनीकरण के इस तरह के कदमों की संसदीय छानबीन की उम्मीद भी न रखें। ऐसे मामले में इस सदन के सामूहिक विवेक का इस्तेमाल करने की अपेक्षा भी न करें? सरकार ने इस फैसले को भी एक गहरा राज़ बनाकर रखा है । कारखानों की मजदूर यूनियनों तक को विश्वास में नहीं लिया और न ही श्रमिकों को विश्वास में लिया, जिनके पसीने से ये उद्योग खड़े हुए हैं। मैं सरकार को याद दिलाना चाहती हूं कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का बुनियादी फर्ज़ लोक कल्याण है, निजी पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, पंडित जवाहर लाल नेहरू ने हमारे सावर्जनिक क्षेत्र के उद्योगों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। आज यह देखकर अफसोस होता है कि इस तरह के ज्यादातर मंदिर खतरे में हैं। मुनाफे के बावजूद उनके कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है और कुछ खास पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए उन्हें संकट में डाल दिया गया है । एचएएल, बीएसएनएल और एमटीएनएल के साथ क्या हो रहा है, यह किसी से भी छिपा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके ज़रिए सरकार से अनुरोध करती हूं कि वे रायबरेली की मॉडर्न कोच फैक्ट्री और सार्वजनिक क्षेत्र की सभी संपत्तियों की पूरी रक्षा करें और उन्हें इस मंजिल तक पहुंचाने वाले श्रमिकों और उनके परिवारों के प्रति सम्मान और आदर का भाव रखें। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले और श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि को श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।